डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जनवरी, 2023, डिस्पेच दिनांक 16 जनवरी, 2023

| वर्ष 66 | अंक 16 | भोपाल | 16 जनवरी, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी : प्रधानमंत्री

आगामी चार-पाँच वर्ष में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनेगा

विश्व भर के निवेशकों के लिए भारत आकर्षण का केंद्र

प्रमोशन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ लें, भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से जुड़ें

नई संभावनाएँ इंतजार कर रही हैं, भारत में निवेश करें

उद्योगों के लिये 24 घंटे में आवंटित करेंगे भूमि : मुख्यमंत्री श्री चौहान

गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट रूप से शामिल हुए

भोपाल : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। सभी पूरी गति से विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश का सामर्थ्य और संकल्प निर्णायक भूमिका निभाएगा। आस्था, अध्यात्म से लेकर पर्यटन तक और कृषि, शिक्षा से लेकर दक्षता संवर्धन तक मध्यप्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी। विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में सातवीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का वर्चुअल शुभारंभ किया। गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से शामिल हुए और संबोधन दिया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क से वर्चुअल संबोधन दिया। प्रमुख निवेशकों ने भी मध्यप्रदेश में निवेश के संबंध में अपने विचार रखे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय ही नहीं, दुनिया की हर संस्था, दुनिया का हर विशेषज्ञ भारत की मजबूत होती अर्थ-व्यवस्था को वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में चमकते सितारे की तरह देख रहा है। हमारे मजबूत मेक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था है। आगामी चार-पाँच वर्ष में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था होगी। यह वैश्विक पटल पर भारत का दशक नहीं, बल्कि भारत की शताब्दी है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विश्व भर के निवेशकों के लिए भारत आकर्षण का केंद्र है। इसका कारण है उनका भारत में अदम्य विश्वास।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

कृषि विपणन बोर्ड की राशि का उपयोग विकास कार्यों में हो : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने की बोर्ड के कार्यों की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न निधियों की राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाए। मंडी बोर्ड द्वारा पूर्व में बनाई गई सड़कों का संधारण प्राथमिकता के साथ और तेजी हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंडी अधो-संरचना विकास निधि से कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज की जाए। कृषि अनुसंधान निधि से कृषि विश्वविद्यालयों में बीज एवं परीक्षण तथा कृषि उपज मंडी समितियों में मिट्टी के परीक्षण की सुविधा के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन और उद्यानिकी फसलों की नई प्रजातियों की रोपण सामग्रियों का और परीक्षण की सुविधा के लिए अधो-संरचनाओं का निर्माण किया जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निधि से निर्माण कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया नियमानुसार की जाए। बोर्ड द्वारा मंडी निधि से 1 हजार 107 किलोमीटर सड़क अभी तक बनाई गई है, जिसमें से 210 किलोमीटर सड़क एमपीआरआरडीए को हस्तांतरित की गई है। शेष 698 किलोमीटर सड़क एमपीआरआरडीए को अंतरित किए जाने का कार्य शीघ्रता से करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बोर्ड की विभिन्न निधियों की जानकारी प्राप्त की। इसमें किसान सड़क निधि, आरआरडीए की अंश राशि, मंडी बोर्ड की अंश राशि आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गौ-संवर्धन निधि, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण निधि, प्रचार-प्रसार एवं कृषक सम्मेलन निधि सहित विभिन्न निधियों का उपयोग समय-सीमा में सुनिश्चित कर लिया जाए।

पेसा नियमों का क्रियान्वयन जल्द से जल्द करना है सुनिश्चित : मुख्यमंत्री

जनजातीय भाई-बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में सामाजिक क्रांति हैं पेसा नियम

मुख्यमंत्री ने किया जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के पोर्टल का शुभारंभ

जनजातीय मंत्रणा परिषद की हुई बैठक

मुख्यमंत्री श्री चौहान का पेसा नियम लागू करने के लिए परिषद ने माना आभार

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा नियम जनजातीय भाई-बहनों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सामाजिक क्रांति हैं। अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी का गाँव-गाँव तक विस्तार करने के लिए युवाओं को जोड़ कर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। मैं स्वयं भी जनजातीय विकासखंडों में जाऊँगा। हमें हर हाल में पेसा नियमों का क्रियान्वयन जल्द से जल्द सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश जनजातीय मंत्रणा परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के पोर्टल का शुभारंभ भी किया। संचालनालय, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, द्वारा बैठक में पेसा नियमों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही परिषद के सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा भी हुई। परिषद ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का पेसा नियम लागू करने के लिए आभार माना।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि 268 ग्राम सभाओं ने तेन्दूपत्ता तोड़ने और बेचने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। आरंभ में इस गतिविधि में वन विभाग पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। पेसा नियम प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखंडों में लागू हैं। प्रदेश के सभी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पेसा नियम के प्रावधान लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इस दिशा में कार्य के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। वृक्षा-रोपण गतिविधियों में वनोपज देने वाले पौधों को लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जनजातीय नृत्य, गायन तथा वादन जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण के लिए विशेष छात्रावास विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा। जनजातीय भाई-बहनों को कोदो-कुटकी का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस दिशा में भी प्रयास होंगे।

बैठक में प्रदेश के जनजातीय युवाओं के स्व-रोजगार व विकास के लिए आरंभ तीन नवीन योजनाओं भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना संबंधी जानकारी दी गई। रतलाम ग्रामीण विधायक श्री दिलीप मकवाना तथा परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा सभी जनजातीय क्षेत्रों में पेसा नियम लागू करने का अनुरोध किया। बैठक में जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा में वृद्धि, आउट सोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की व्यवस्था, शिक्षकों के अध्यापन स्तर के मूल्यांकन, जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूल आरंभ करने संबंधी भी चर्चा हुई। डॉ. रूपनारायण माडवे, श्री राम दांगोरे तथा श्री कालू सिंह मुजालदा के सुझावों पर चर्चा हुई।

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण तथा पशुपालन मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित अपर मुख्य सचिव और सचिव उपस्थित थे।

कृभको के किसान समृद्धि केन्द्र पर किसानों को मिलेंगी सुविधाएं

देवास। केन्द्रीय एवं रसायन उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉ. मनसुख मांडवीया ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों से सीधे चर्चा के दौरान कृभको देवास स्थित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर देवास जिले के प्रगतिशील किसान श्री धर्मेन्द्र राजपूत ग्राम छोटी चुरलाय से लाइव आकर उक्त केन्द्र से किसानों को मिलने वाली सुविधा एवं खेती किसानी व उर्वरक आवश्यकता एवं आपूर्ति के विषय में चर्चा की। इस अवसर पर कृभको देवास द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर वृहत फसल संगोष्ठी (प्रमाणित बीज व उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम) का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में श्री आर. पी. कनेरिया उपसंचालक कृषि जिला देवास, डॉ. ए.के. बडाया, प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र देवास, श्री परमानन्द गोडरिया, उपायुक्त सहकारिता, देवास, श्री जे.पी. सिंह उपमहाप्रबंधक कृभको म.प्र. भोपाल, श्री पी.के. अवस्थी वरि. प्रबंधक कृभको नोएडा, श्री जी.पी. शर्मा, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, कृभको इंदौर, डॉ. सविता कुमारी एवं डॉ. निशीत गुप्ता वैज्ञानिक केवीके देवास उपस्थित थे।कार्यक्रम का संचालन श्री विनायक हरोड़ कृभको रतलाम एवं आभार प्रदर्शन श्री राहुल पाटीदार कृभको देवास द्वारा किया गया।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने किया मध्यप्रदेश एक परिचय पुस्तक का विमोचन

भोपाल : सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने 'मध्यप्रदेश एक परिचय' पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने पुस्तक के लेखक श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया को शुभकामनाएँ दी। पुस्तक में मध्यप्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं।

पशुपालन की राष्ट्रीय योजनाओं में अग्रणी है मध्यप्रदेश

भोपाल : पशुपालन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। अन्य राज्यों के लिए मध्यप्रदेश मॉडल राज्य के रूप में उभरा है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश में 2 करोड़ 92 लाख 51 हजार गौ-भैंस वंशीय पशु पंजीकृत हैं। इन पशुओं को यूआईडी टैग लगा कर इनॉफ पोर्टल पर दर्ज किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है।

एफएमडी (मुंहपका खुरपका रोग) टीकाकरण में भी मध्यप्रदेश देश में प्रथम है। प्रदेश में पहले चरण में 2 करोड़ 50 लाख 63 हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। दूसरे चरण में टीकाकरण जारी है। माह नवंबर के प्रथम सप्ताह तक 36 लाख 14 हजार पशुओं का टीकाकरण किया गया।

मध्यप्रदेश ब्रुसेल्ला टीकाकरण में भी देश में शीर्ष पर है। पहले चरण में 4 से 8 माह की 17 लाख 45 हजार गौ-भैंस वंशीय बछियों का टीकाकरण किया गया। दूसरे चरण में 7 नवंबर 2022 तक 39 जिलों के 10 लाख 50 हजार बछियों का टीकाकरण किया जाकर इनॉफ (इंफारमेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टविटी एण्ड हेल्थ) पोर्टल में जानकारी दर्ज की जा चुकी है।

केन्द्र सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य व्यवसायिक किसानों की कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार किया गया है। इसमें भी मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रव्यापी केसीसी अभियान में 2 दिसम्बर 2022 तक प्रदेश के 2 लाख 5 हजार 70 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किये गये हैं। पशुपालकों को जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज अनुदान पर कार्यशील पूँजी के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम में बकरी, सूकर, मुर्गी पालन और चरी-चारा के लगभग 1860 से अधिक प्रस्ताव विभाग को ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 27 प्रकरणों में केन्द्र सरकार से अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है।

आत्म निर्भर मध्यप्रदेश बनाने की मजबूत पहल है प्रदेश की स्टार्ट अप नीति

भोपाल : मध्यप्रदेश की स्थापना के 67 साल बाद ही सही प्रदेश का औद्योगिक परिवेश अब लगातार और लगातार बेहतर हो रहा है। बेहतरी की इसी कड़ी में नया आयाम है, राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्टार्टअप्स के लिए एक जीवंत और अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करने की प्रतिबद्धता।

7 से 2435 स्टार्ट अप की ग्रोथ

पिछले कुछ समय में ही मध्यप्रदेश को युवाओं, निवेशकों और भारत सरकार से लगातार मिले समर्थन से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट-अप गतिविधियों में आशा से अधिक वृद्धि देखी गई है। प्रदेश में वर्ष 2016 में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त सिर्फ 7 स्टार्टअप थे, अब डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त लगभग 2584 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश में हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनमें 44% से अधिक स्टार्टअप की प्रवर्तक महिलाएँ हैं। मध्यप्रदेश के स्टार्टअप्स एरोनॉटिक्स, रक्षा, कृषि, ए.आई. एनीमेशन, फैशन, फिन-टेक, खाद्य प्र-संस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत है। इन स्टार्टअप में शीर्ष 5 क्षेत्र आईटी परामर्श, निर्माण और इंजीनियरिंग, कृषि-तकनीक, खाद्य प्र-संस्करण, व्यवसाय सहायता सेवाएँ प्रमुख हैं। प्रदेश के अधिकांश स्टार्टअप ने पिछले 6 वर्षों में धीरे-धीरे आईडीएशन स्टेज से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद आज सफल व्यवसाय स्थापित कर महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है।

प्रदेश का स्टार्टअप ईकोसिस्टम अब मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के नियमों के अंतर्गत काम करने लगा है। पॉलिसी का क्रियान्वयन एमएसएमई विभाग कर रहा है। विभाग अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

डीपीआईआईटी द्वारा जारी 'राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग' के दोनों संस्करण में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है।

यही नहीं राज्य के स्टार्टअप ईकोसिस्टम की और भी कई उपलब्धियाँ रही हैं। स्टार्टअप से जुड़े सभी हितधारकों जैसे स्टार्ट-अप, इनक्यूबेटर, सेंटर, निवेशक, स्टार्ट-अप पार्टनर, राज्य सरकार और एमपी स्टार्टअप सेंटर को स्टार्टअप पोर्टल से जोड़ा गया है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर पहले से पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप, अपने मौजूदा लॉग-इन का उपयोग कर एमपी स्टार्ट अप पोर्टल में प्रवेश कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश की स्टार्ट अप नीति

मध्यप्रदेश का स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम विभिन्न क्षेत्र के स्टार्ट-अप के वर्गीकरण के साथ विकसित हुआ है। राज्य सरकार ने इसके लिये एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया है। नई नीति में स्टार्ट-अप के लिए कई प्रक्रियाओं को सरल और आसान बनाया गया है। सार्वजनिक खरीद को आसान बनाने से लेकर नई स्टार्ट अप नीति में इनक्यूबेटरों को ज्यादा समर्थन की पेशकश की गई है। नई नीति एक मजबूत वित्त पोषण तंत्र का विकास भी करती है। साथ ही ग्रामीण नवाचार को संगठित करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में भी स्टार्ट अप के प्रति अधिकतम जागरूकता और पहुँच पैदा करती है।

प्रदेश की नीति के प्रमुख तत्वों में से एक प्रदेश के स्टार्टअप सेंटर की स्थापना है। यह सेंटर राज्य के स्टार्ट-अप को सुविधाएँ और जरूरी सहायता देगा। सेंटर राज्य में स्टार्ट-अप तंत्र को बढ़ावा देने, उन्हें मजबूत करने और सुविधा देने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में काम करेगा।

मध्यप्रदेश की स्टार्ट अप नीति 2022 की अनेक विशेषताएँ हैं, जो इसे देश में अलग पहचान देती है। संस्थागत रूप से विषय-विशेषज्ञों के साथ मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना, मजबूत ऑनलाइन पोर्टल का विकास, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जरूरी शैक्षणिक सहायता का आदान-प्रदान का प्रावधान नीति की विशेषताएँ हैं।

मध्यप्रदेश की नीति स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर दोनों के लिए राजकोषीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों में समन्वय करती है। इस नीति में संस्थागत विपणन, वित्तीय और व्यावसायिक सुविधा स्टार्ट-अप और इनक्यूबेटर ईकोसिस्टम को विकसित और उन्हें जरूरी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता के रूप में नीति में सेबी, आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से सफलतापूर्वक निवेश प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 लाख रूपए तक की सहायता दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम 4 बार दी जाएगी। इसी तरह महिलाओं के स्टार्ट-अप के लिए 20 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान है। फंड जुटाने की प्रक्रिया में स्टार्टअप्स का सपोर्ट करने वाले इन्क्यूबेटरों को इनके अलावा 5 लाख रूपए तक की सहायता दी जाएगी। ईवेंट आयोजन के लिए संबंधित राज्य के इन्क्यूबेटरों को प्रति ईवेंट 5 लाख रूपए तक की सहायता दी जाएगी। इसकी सीमा अधिकतम प्रति वर्ष 20 लाख रूपए होगी। इन्क्यूबेटरों की क्षमता वृद्धि के लिए 5 लाख रूपए तक की सहायता दी जाएगी। मासिक लीज रेंटल के लिए 50 प्रतिशत तक की सहायता अधिकतम 5000 रूपए प्रति माह तीन वर्ष के लिए दी जाएगी। पेटेंट प्राप्त करने के लिए भी 5 लाख रूपए तक की सहायता दिए जाने का प्रावधान नीति में है।

उत्पाद-आधारित स्टार्ट-अप के लिए विशेष वित्तीय सहायता में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति 13000 रूपये तक प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष 3 वर्ष के लिए और रोजगार सृजन के लिए 5000 रूपये प्रति कर्मचारी प्रति माह की सहायता, अधिकतम 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। कनेक्शन की तारीख से 3 साल के लिए बिजली शुल्क में छूट एवं नए बिजली कनेक्शन के लिए 5 रूपए प्रति यूनिट की दर 3 साल के लिए निर्धारित किए जाने का प्रावधान है।

स्टेट इनोवेशन चैलेंज के तहत वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक समस्या को हल करने वाले चुने हुए चार स्टार्टअप को प्रति स्टार्टअप एक करोड़ रुपये तक चार चरण में अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अब नीति अनुसार विपणन के क्षेत्र में 1 करोड़ रूपए तक की खरीदी में अनुभव एवं टर्नओवर से संबंधित छूट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की निविदाओं और अनुरोध के प्रस्ताव के लिए जमानत राशि से छूट के साथ ही स्टार्ट-अप को केन्द्र से टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना भी महत्वपूर्ण है।

2.5 लाख से अधिक फर्टिलाइजर दुकानें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र में बदलेंगी

डॉ. मांडविया ने देश भर के 9000 से अधिक किसानों और खुदरा विक्रेताओं से वर्चुअली बातचीत की

नई दिल्ली। भारत सरकार किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम उठा रही है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कदम के रुप में, उर्वरक खुदरा दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों (पीएमकेएसके) में परिवर्तित किया जा रहा है। ये पीएमकेएसके कृषि संबंधी सभी कार्यों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेंगे और नवीनतम नवाचारों, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, ज्ञान, तकनीकों और परीक्षणों का प्रसार करेंगे जो किसानों को न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ाने बल्कि उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करेंगे। यह बात केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देश भर के लगभग 9000 पीएमकेएसके के एकत्र किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। उन्होंने छह राज्यों रामनगर (उत्तर प्रदेश), कोटा (राजस्थान), देवास (मध्य प्रदेश), वडोदरा (गुजरात) के पीएमकेएसके के किसानों और खुदरा विक्रेताओं और एलुरु (आंध्र प्रदेश) और राजापुरा (पंजाब) के खुदरा विक्रेताओं के साथ भी बातचीत की।

डॉ. मांडविया ने कहा देश में लगभग 2,62,559 सक्रिय खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से पीएमकेएसके में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 'रूपांतरण की यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि पीएमकेएसके में प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला देश के सभी किसानों तक पहुंचे। पीएमकेएसके भविष्य में किसानों के लिए एक प्रमुख मंच साबित होगा जो किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने में मदद करेगा और कम से कम समय में उनकी चिंताओं को दूर करेगा।'

इस अवसर पर, डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत सरकार किसानों को समर्थ बनाने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए समर्पित है। चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता हो, या नैनो यूरिया और वैकल्पिक उर्वरकों के नए वैज्ञानिक नवाचार, व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उर्वरकों की उपलब्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद, सरकार अत्यधिक रियायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

पीएमकेएसके के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 'पीएमकेएसके खोलना एक बड़ा कदम है, जो किसानों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा जैसे कृषि संबंधी जानकारी (उर्वरक, बीज और कीटनाशक) प्रदान करना और मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना। कार्यक्रम के दौरान श्री अरुण सिंघल, सचिव, उर्वरक विभाग, सुश्री नीरजा आदिदम, अपर सचिव सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

किसानों की आय दोगुनी करने के हरसंभव प्रयास वर्ष 2022 में किए

नई दिल्ली। देश में किसानों की आय दोगुनी करने तथा प्रत्येक किसान हित की योजनाओं का जमीनी स्तर तक लाभ पहुँचाने के लिए बीते वर्ष 2022 में सरकार ने हरसंभव प्रयास किए। बजट में वृद्धि करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में वृद्धि, किसानों को वार्षिक सहायता, कृषि अवसंरचना फंड, एफपीओ, नवाचारों का प्रयोग, किसान रेल तथा स्टार्ट अप इको सिस्टम बनाए गए। वर्ष भर चली इन गतिविधियों से एक ओर जहाँ किसानों को आर्थिक सम्बल मिला वहीं दूसरी ओर ड्रोन जैसी नई तकनीक से उन्नत खेती कर उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की। वर्ष 2022 में केन्द्र सरकार द्वारा कृषक हित में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसमें मुख्यत: कृषि एवं सम्बंध क्षेत्र के लिए बजट में 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपए रखे गए, जिससे भरपूर राशि मिलती रही और कृषि कार्य होते रहे।

बजट बढ़ाया

कृषि मंत्रालय के लिए 2022-23 में बजट बढ़ाकर 1 लाख 24 हजार करोड़ कर दिया गया है।

डेढ़ गुना एमएसपी तय

- सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारतीय औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की।
- धान (सामान्य) के लिए एमएसपी 1940 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। वहीं गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।

किसानों से उपज खरीद बढ़ी

- वर्ष 2020-21 के लिए, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 लाख 11 हजार मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की, जिसका एमएसपी 6,830 करोड़ रुपये है, जिससे 7 लाख 6 हजार 552 किसानों को लाभ हुआ, जबकि वर्ष 2021-22 में 31 लाख 8 हजार मीट्रिक टन दलहन, तिलहन और खोपरा जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 17 हजार करोड़ रुपये था उसने 14 लाख 68 हजार किसानों को लाभान्वित किया है। इसके अलावा, खरीफ 2021-22 मौसम के तहत जनवरी, 2022 तक खरीदे गए 2 लाख 24 हजार मीट्रिक टन दलहन और तिलहन जिसका एमएसपी 1380 करोड़ रुपये था उससे 1 लाख 37,788 किसान लाभान्वित हुए जबकि खरीफ 2022-23 खरीद मौसम के तहत दिसम्बर 2022 तक 915.79 करोड़ रुपये मूल्य की एमएसपी पर 1 लाख 3 हजार 830 मीट्रिक टन दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद की गई जिससे 61,339 किसानों को लाभ मिला है।

पीएम किसान से सहायता

- पीएम-किसान योजना में जनवरी 2022 में 11.74 करोड़ से अधिक किसानों को 1.82 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि दिसम्बर, 2022 तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए जा चुके हैं।

कृषि के लिए संस्थागत ऋण

- कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋ ण जनवरी 2022 में 16.5 लाख करोड़ रुपये था, जिसे दिसम्बर, 2022 में बढ़ाकर 18.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- 4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर केसीसी के माध्यम से संस्थागत ऋण का लाभ पशुपालन की और मछली पालन को मिलेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को शामिल करने पर एक विशेष अभियान के तहत जनवरी, 2022 तक 3 लाख 19 हजार 902 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के साथ 291.67 लाख नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए थे, जो दिसम्बर, 2022 में 4 लाख 33 हजार 426 करोड़ रुपये की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ अभियान के हिस्से के रूप में बढ़कर 376.97 लाख स्वीकृत केसीसी आवेदन हो गए।

एग्री इंफ्रॉस्ट्रक्चर फंड

- छोटे एवं कम पूंजी वाले उद्योग धंधों तथा कृषि में अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए केन्द्र द्वारा एग्री इंफ्रॉस्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की स्थापना के बाद से दिसम्बर 2022 तक देश में 18,133 से अधिक परियोजनाओं के लिए 13,681 करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई।
- दिसम्बर 2022 तक 8076 गोदामों, 2788 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, 1860 कस्टम हायरिंग केन्द्रों, 937 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, 696 कोल्ड स्टोर परियोजनाओं, 163 परख इकाइयों और लगभग 3613 अन्य प्रकार की फसल कटाई के बाद की प्रबंधन परियोजनाओं और सामुदायिक कृषि संपत्तियों तक बढ़ गई।

मुर्गियों के लिए विकसित टीका एच9एन2 तकनीक का हस्तांतरण

नई दिल्ली। आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 'मुर्गियों के लिए निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (एच9एन2) टीके' को मेसर्स ग्लोबियन इंडिया प्रा. लि., सिकंदराबाद, मेसर्स वेंकटेश्वर हैचरीज प्रा. लि., पुणे, मेसर्स इंडोवैक्स प्रा. लि., गुड़गांव और मेसर्स हेस्टर बायोसाइंसेज लि., अहमदाबाद को हस्तांतरित कर दिया गया। यह सुविधा एनएएससी, नई दिल्ली में एग्रीनोवेट इंडिया लि. (एजीआईएन) द्वारा प्रदान की गई।

इस कार्यक्रम में डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव (डीएआरई) तथा महानिदेशक (आईसीएआर) एवं अध्यक्ष, एजीआईएन, डॉ. बी.एन. त्रिपाठी, डीडीजी (पशु विज्ञान), डॉ. प्रवीण मलिक, सीईओ, एग्रीनोवेट इंडिया लि., डॉ. अनिकेत सान्याल, निदेशक आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, वाणिज्यिक फर्मों के प्रतिनिधि, आईसीएआर और एजीआईएन के अन्य अधिकारी शामिल हुए।

डॉ. हिमांशु पाठक ने एच9एन2 वायरस के लिए पहले स्वदेशी टीके के विकास में आईसीएआर-एनआईएचएसएडी के वैज्ञानिकों के गंभीर प्रयासों की सराहना की और उद्योग जगत को इसके प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण संबंधी प्रयासों के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लि. (एजीआईएन) की सराहना की।

डीडीजी (एएस) ने जोर देकर कहा कि यह टीका भारत और विदेश दोनों ही बाजारों के मानकों पर खरा उतरेगा। यह टीका बीमारी से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करके मुर्गीपालन में संलग्न किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मध्य प्रदेश में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने होंगे फ़ूड फेस्टिवल, रोड शो

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का केलेण्डर जारी

भोपाल: संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2023 को मध्य प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने के लिये केलेण्डर जारी कर दिया गया है। इस वर्ष विभिन्न विभागों द्वारा मोटे अनाज (मिलेट) के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिये व्यापक गतिविधियाँ की जायेंगी। संबंधित विभागों के लिये विभागीय गतिविधियाँ तय कर दी गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में प्रदेश की मोटे अनाज (मिलेट) फसलों का निरंतर और व्यापक प्रचार-प्रसार होगा। मिलेट वर्ष में मिलेट संबंधित उत्पादन, विपणन तथा मिलेट फसलों के प्रति आमजन में रूचि उत्पन्न करने के लिये विभिन्न विभागों की माहवार गतिविधियों का केलेण्डर तैयार कर जारी किया गया है। इसके लिये समय-समय पर अंतर्विभागीय बैठक भी होगी।

कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, राज्य जैविक प्रमाणीकरण बोर्ड, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, एपीडा, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, दूरदर्शन, आकाशवाणी और जनसम्पर्क विभाग की भूमिकाएँ तय की गई हैं।

जनवरी माह की गतिविधियाँ

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के प्रचार-प्रसार के लिये जनवरी माह में राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम-पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियाँ होंगी। राज्य-स्तर पर फूड फेस्टिवल, रोड-शो और मिलेट पर वर्कशॉप होंगी। प्रदेश के जिलों में विशेष रूप से आयोजित मेलों और महोत्सवों में मिलेट गतिविधियाँ होंगी। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सेमीनार/वेबिनार किये जायेंगे। म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में माह में एक दिवस मिलेट्स आधारित व्यंजन प्रदर्शित कर परोसे जायेंगे। जिला और विकासखण्ड-स्तर पर शासकीय विद्यालयों में मिलेट्स आधारित रंगोली/पोस्टर्स निर्माण/स्लोगन पर प्रतियोगिता होगी। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कृषि विज्ञान केन्द्र एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा मिलेट के लाभ आदि संबंधी में व्याख्यान होंगे। ग्राम पंचायतों में 26 जनवरी 2023 को होने वाली ग्राम सभा में मिलेट फसलों को भोजन में शामिल कर इसके लाभों से लोगों को अवगत कराया जायेगा।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण विषय पर प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल में 31 दिसंबर 2022 को संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहकारिता से संबंधित नई जानकारियों से संघ के प्रशिक्षकों को अद्यतन करने के साथ–साथ, प्रशिक्षण की नई तकनीक का ज्ञान एवं प्रशिक्षण को प्रभावी कैसे बनाए जाए इन सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में कुल 35 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

राज्य सहकारी संघ का प्रमुख कार्य सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षा – प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार है। संघ यह कार्य प्रशिक्षण केन्द्रों में अल्पावधि कोर्स आयोजित कर तथा संघ के चलित प्रशिक्षक विभिन्न सहकारी समितियों में जा कर समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जैसे – समिति कार्य संचालन, समिति के कार्यों में आने वाली समस्याओं का निराकरण, समिति का लेखा–जोखा, समिति की बैठकों, आमसभा का संचालन, निर्वाचन, अंकेक्षण, कर्मचारियों से संबधित विभिन्न विषय आदि।

प्रशिक्षण का शुभारंभ राज्य सहकारी संघ मुख्यालय भोपाल में संघ के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह के उद्‌बोधन द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में पीपुल्स यूनिवर्सिटी के प्राचार्य डॉ. पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रशिक्षक को प्रभावी कैसे बनाएं, प्रशिक्षक की बॉडी लैंग्वेज, वेशभूषा, सम्प्रेषण कलां, व्यक्तित्व विकास, प्रशिक्षण प्रबंधन, प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान कैसे करें इत्यादि विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में संघ के महाप्रबंधक द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में हुए नवीन परिवर्तनों एवं भारत में नवीन सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद प्रदेश के सहकारी क्षेत्र से क्या अपेक्षाएं हैं तथा क्या नवीन योजनाएं लागू की जा रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो रहे सहकारिता के डाटाबेस हेतु किन जानकारियों का संकलन प्रशिक्षण के दौरान किया जा सकता है, इस पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। संघ के शोध अधिकारी श्री अविनाश सिंह द्वारा सहकारी समितियों के कार्य संचालन के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं एवं उनके निराकरण के बारे में जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन राज्य समन्वयक श्री संतोष येड़े एवं कार्यक्रम का समन्वय श्रीमती रेखा पिप्पल, व्याख्याता द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे तेंदूपत्ता संग्राहकों को सामग्री का वितरण

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के विभिन्न जनजातीय बहुल क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े लोगों को चरण पादुका, वस्त्र और अन्य सामग्री का वितरण करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में घोषणा की थी। प्रदेश के विंध्य और महाकौशल अंचल के साथ अन्य स्थानों पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, अपर मुख्य सचिव वन श्री जे.एन. कंसोटिया और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में विचार-विमर्श किया। सामग्री वितरण के साथ ही महिला स्व-सहायता समूह द्वारा लोक-नृत्य, अन्य स्पर्धाओं में भागीदारी के कार्यक्रम की रूपरेखा और आगामी अप्रैल माह में प्रस्तावित वन महोत्सव पर भी चर्चा हुई।

वन्य-प्राणी संरक्षण प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में वन्य-प्राणियों के संरक्षण के साथ मनुष्य और पशुओं के अस्तित्व के संतुलन को भी सदैव ध्यान में रखा जा रहा है। वन्य-प्राणियों का शिकार करने वाले आपराधिक तत्वों पर पूरी तरह अंकुश रहे। इस संबंध में वन विभाग का अमला हमेशा सजग रहे। वन्य-प्राणियों के शिकार के दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए।

गेहूं की फसल को जड़ माहू कीट तथा सरसों की फसल को माहू से बचाएं

विदिशा : वर्तमान समय में कही-कही सरसों फसल में माहू तथा गेहूं फसल में जड़ माहू कीट के प्रकोप होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतरू किसान भाई अपने खेत की सतत निगरानी करें।

जड़ माहू कीट के लक्षण

यह कीट गेहूं फसल में पौधों की जड़ों से रस चूसता है जिसके कारण पौधा पीला पड़ने लगता है। और धीरे-धीरे सूखने लगता है। शुरूआत में खेतों में जगह-जगह पीले पड़े हुय पौधे दिखाई देते हैं, बाद में पूरा खेत सूखने की संभावना रहती है।

जड़ माहू कीट की पहचान

यह कीट हल्के पीले रंग से गहरे हरे रंग का होता है जो जड़ों का रस चूसता हुआ दिखाई पड़ता है। गेहूं के पौधों को जड़ से उखाड़ने पर ध्यागनपूर्वक देखने से यह कीट आसानी से दिखाई देता है।

जड़ माहू कीट प्रबंधन

इस कीट के प्रबंधन हेतु इमीडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. दवा की 70 एम.एल. मात्रा प्रति एकड़ अथवा एसीटामेप्रिड 20 प्रतिशत एस.पी. दवा की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ अथवा थायोमिथाक्जॉरम 25 प्रतिशत डब्ल्यूजी दवा की 50 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150-200 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे खेत में अच्छी तरह से छिड़काव करें। यह दवाएं सिस्टेमिक प्रकार की होती है जिनसे पूरा पौधा जहरीला हो जाता है और जब कीट या रस चूसता है तो वह मर जाता है।

सरसों में माहू प्रबंधन

सरसों में माहू पत्तियों, कोमल भागो, फूलों एवं पत्तियों से रस चूसते है जिससे उपज कम हो जाती है। जब इस कीट का प्रकोप औसतन 10 प्रतिशत पौधों पर या 25 कीट प्रति पौधा से ज्यादा हो जाये तो इनमें से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करें। एसीटामेप्रिड 20 प्रतिशत की 100-150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ का छिड़काव करे या थायोमिथाक्जॉमे 25 प्रतिशत की 100-150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ का छिड़काव करे यदि जरूरत हो तो छिड़काव को दोहराएं।

माटीकला योजनान्तर्गत शिल्पी कारिगरों के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

राजगढ़ : सहायक संचालक हाथकरघा द्वारा दी गई जानकारी अनुसार राजगढ़ जिले में माटीकला योजनान्तर्गत शिल्पी कारिगरों के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। म.प्र. माटीकला बोर्ड द्वारा प्रदेश में कार्यरत माटीकला शिल्प से संबंधित कारीगरों की पहचान स्थापित करने हेतु पंजीयन की प्रक्रिया की जा रही है। जिले में कार्यरत माटीशिल्प कारीगर, कुम्हारों से संबंधितत स्व-सहायता समूह इकाई पंजीकृत संस्था तथा व्यक्तिगत उद्यमियों से आवेदन पत्र जिले के पदेन अधिकारी महाप्रबंधक माटीकलां बोर्ड जिला कार्यालय सारंगपुर में आमंत्रित किए गए है। जिला अधिकारी माटीकलां बोर्ड एवं सहायक संचालक हाथकरघा श्री सेजमल ने बताया कि पंजीयन म.प्र. माटीकलां बोर्ड भोपाल द्वारा आवश्यक दस्तावेज के पूर्ण होने पर पात्रतानुसार ही पहचान पत्र जारी किए जाएगे। पंजीयन प्राप्त माटी शिल्पीयों एवं कारीगरों को शासन से प्राप्त होने वाली सुविधाओं जैसे उत्पादित सामग्री एवं विक्रय में आने वाली सुविधा एवं उत्पादकों के मांग के अनुरूप नवीन विधाओं आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण प्रदाय करना आदि सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इच्छुक शिल्पी पंजीयन की पात्रतानुसार निर्धारित प्रारूप में जिले के पदेन अधिकारी, सहायक संचालक जिला हाथकरघा कार्यालय सारंगपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साईज फोटो, शपथ पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार समग्र आई.डी., बैंक पासबुक की छायाप्रति आवेदन पत्र में रहेगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका ...

भारत में सशक्त प्रजातंत्र है, युवा शक्ति है, राजनैतिक स्थिरता है, तेजी से निर्णय लेने की क्षमता है, ईज ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। भारत रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मार्ग पर चल रहा है। भारत में विकास की अभूतपूर्व गति है। वर्ष 2014 से हम तेज गति से आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेश के लिए हर आवश्यक सुविधा है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, श्रम कानूनों को सरल किया गया है, विभिन्न पाबंदी हटाई गई है, आधुनिक और मल्टी मॉडल अधो-संरचना है, दुनिया का सबसे प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक मार्केट है, नई लॉजिस्टिक नीति लागू है, गाँव-गाँव में ऑप्टिकल फाइबर है, 5G नेटवर्क है, बीते 8 वर्षों में हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की गति दोगुना हो गई है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या भी दोगुनी हो चुकी है, हमारे पास डेडीकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक्सप्रेस-वे हैं, लॉजिस्टिक पार्क हैं, हमारी पोर्ट क्षमता भी बढ़ी है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान अधो-संरचना विकास का राष्ट्रीय प्लेटफार्म है। बैंकिंग सेक्टर का री-केपिटलाइजेशन किया गया है, वन नेशन-वन टैक्स है, कई क्षेत्रों में शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नया भारत प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी पूरा भरोसा करता है। अब निजी क्षेत्र के दरवाजे रक्षा, खनिज, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्रों के लिए भी खोल दिए गए हैं। ये सब हमारी विकास की गति को तेज करेंगे और मेक इन इंडिया को नई ताकत प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए प्रमोशन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) लागू की गई है, जो अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है। इस योजना में अभी तक ढ़ाई लाख करोड़ इंसेंटिव्स की घोषणा की गई है, चार लाख करोड़ का उत्पादन हुआ है। मध्यप्रदेश में भी इस योजना का लाभ लेते हुए सैकड़ों करोड़ का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों से कहा कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी को लेकर भी भारत में तेज गति से कार्य हो रहा है। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसमें 8 लाख करोड़ रूपये निवेश की संभावना है। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी मिशन है, जो ऊर्जा की वैश्विक आवश्यकता को पूरा करेगा। इससे जुड़ कर हजारों करोड़ रूपये के इंसेंटिव्स का लाभ लें। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने निवेशकों से कहा कि निवेश के क्षेत्र में कई नई संभावनाएँ आपका इंतजार कर रही हैं। यह भारत के साथ नई ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्माण का समय है। भारत में अधिक से अधिक निवेश करें।

सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से कार्य कर रहे है। अर्थ-व्यवस्था में सुधार के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। भारत नेतृत्व कर रहा है। सूरीनाम भारत के साथ विभिन्न क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग करेगा।

गुयाना के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद इरफान अली ने कहा कि वे मध्यप्रदेश आकर और मुख्यमंत्री श्री चौहान से मुलाकात कर प्रसन्न है। मध्यप्रदेश में सुशासन और अच्छी नीतियों के कारण विकास की गति बढ़ी है। इंदौर शहर की स्वच्छता और सुंदरता का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इन विशेषताओं के कारण मध्यप्रदेश में अनेक उद्योग आ रहे हैं। गुयाना भी औद्योगिक विकास में भागीदार बनेगा। राष्ट्रपति श्री अली ने गुयाना के क्रिकेट के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरने का उल्लेख किया।

उद्योगों के लिये 24 घंटे में आवंटित करेंगे भूमि

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में हो रही यह समिट सही अर्थ में वैश्विक है। इस समिट में जहाँ दो देश सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति आये हैं, वही समिट में मारीशस के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, जिंबॉब्वे के खनिज मंत्री भी आए हैं। विश्व के 33 देश के प्रतिनिधि आए हैं। कुल 84 देश के 431 डेलिगेट्स आए हैं। आज मध्यप्रदेश की विशेषताओं की विशेष चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए तैयार वातावरण से उद्योगपति परिचित हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक समय मध्यप्रदेश बीमारू राज्य था। जब इंदौर के सुपर कॉरीडोर और सड़कों की चर्चा होती थी तो मैं अमेरिका से तुलना करता था। आज विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधि स्वच्छता सहित बुनियादी क्षेत्रों में हुए कार्य को देख रहे हैं। हरियाली और पर्यावरण-संरक्षण के लिये निरंतर कार्य हो रहा है। अब गेहूँ सहित मध्यप्रदेश के अन्य उत्पाद निर्यात हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2026 तक 5 ट्रिलियन डालर की अर्थ-व्यवस्था बनाने की बात कही है। इसमें मध्यप्रदेश का योगदान 550 बिलियन डालर से कम नहीं होगा। प्रदेश में 300 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं। अनेक फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क हैं और अब मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी विकसित हो रहे हैं। निवेशक खुद यह मानने लगे हैं कि मध्यप्रदेश निवेश की दृष्टि से अनुकूल है। फार्मा सेक्टर बधाई का पात्र है, जिसने कोविड के संकट के समय निरंतर कार्य कर लोगों के हित में भूमिका निभाई। प्रदेश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र, नवकरणीय ऊर्जा में लगातार कार्य किया गया है। रेडीमेड उद्योग में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर है, शीघ्र ही पहले स्थान पर आने का लक्ष्य है। हमारी बहने और बेटियाँ परिश्रमी हैं। वे तीन शिफ्ट में भी कार्य करती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब ओंकारेश्वर में बांधों की जलराशि की सतह पर तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज पैकेज देने का कार्य भी राज्य सरकार करेगी।

मैं मध्यप्रदेश में सीईओ के रूप में सदैव उपलब्ध हूँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे मध्यप्रदेश के सीईओ के रूप में सदैव उपलब्ध हैं। प्रति सोमवार उद्योगपतियों से भेंट के लिये समय तय किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य है और इंदौर देश का स्वच्छतम शहर है। आज प्रदेश विकास की तरफ तेजी से बढ़ा है। प्रदेश की विकास दर देश में सर्वाधिक है. हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की जीडीपी में मध्यप्रदेश का विशेष स्थान है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 37 हजार हो गई है, लेकिन हमें चैन नहीं है इसलिए मध्यप्रदेश में निरंतर कार्य हो रहा है। प्रदेश को और आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जमीन की माँग 24 घंटे में पूरी करेंगे। प्रदेश में जमीन की पर्याप्त उपलब्धता है। इसे प्राथमिकता से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये प्रदान करने का कार्य किया जायेगा। मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए बनाये गये लैंड बैंक में लगभग 2 लाख एकड़ भूमि की उपलब्धता है। प्रदेश में अनेक खनिज हैं। जहाँ तक ऊर्जा उत्पादन की बात है 25 हजार मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। दिल्ली की मेट्रो रेल भी मध्यप्रदेश की बिजली के सहयोग से चलती है। पानी की कमी नहीं है। औद्योगिक शांति है। प्रदेश से दस्युओं का आतंक समाप्त किया गया है। सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। ब्यूरोक्रेसी सहयोगी है। उद्योग लगाने जो भी आयेंगे उन्हें मंत्रीगण भी सहयोग करेंगे। मध्यप्रदेश में 11 जलवायु क्षेत्र हैं। प्रदेश देश की खाद्य राजधानी के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में अनेक संभावनाओं को हम देख रहे हैं। फिर चाहे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हैरिटेज टूरिज्म हो या धार्मिक पर्यटन हो। मध्यप्रदेश के अनेक पर्यटन-स्थलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कूनों पालपुर में चीतों को बसाने का कार्य सफल हुआ है। फरवरी माह से पर्यटक इन्हें देख सकेंगे। मध्यप्रदेश चीता राज्य बनने के पहले टाइगर, लेपर्ड और क्रोकोडाइल राज्य भी बन चुका है। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक और शिव सृष्टि के दर्शन के लिये पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। समिट में आये अतिथि उज्जैन का भ्रमण अवश्य करें।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अमेरिका से समिट में वर्चुअली जुड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विकास के लिए अर्थ-व्यवस्था की गति को तेज करने का कार्य किया है। मध्यप्रदेश में औद्योगीकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। मध्यप्रदेश में भी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के सुशासन के साथ विकास के विजन को लागू किया गया है। गत साढ़े 8 वर्ष विकास के रहे हैं। आज हमारे पास सरप्लस पावर है। एक राष्ट्र एक ग्रिड के साथ ही वन-नेशन-वन ला और वन नेशन-वन टैक्स की व्यवस्था की पहल हुई है। मुझे आशा है मध्यप्रदेश देश की अर्थ-व्यवस्था को गति प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि मध्यप्रदेश ने इज ऑफ डूइंग और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। मध्यप्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति है। प्रदेश में देश का एक चौथाई ऑर्गेनिक कॉटन होता है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश का योगदान 20% है। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी कार्य हो रहा है। मध्यप्रदेश वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में भी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश को पर्यटन, फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और टेक्सटाईल क्षेत्र में संभावनाओं को साकार करने वाला प्रदेश माना है। श्री गोयल ने उद्योगपतियों और निवेशकों से मध्यप्रदेश में निवेश का आहवान भी किया।

आदित्य बिरला ग्रुप के श्री कुमार मंगलम ने कहा कि मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति प्रदेश को निवेश की दृष्टि से सभी रूप से उपयुक्त बनाती है। हमारे समूह के प्रदेश से ऐतिहासिक संबंध है। समूह का 60 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश में है। औद्योगिक नीति तथा स्टार्टअप भविष्य में निवेश की दृष्टि से उपयुक्त हैं।

एक्ससेंचर की सुश्री रीता मेनन ने कहा कि कौशल उन्नयन के क्षेत्र में प्रदेश की पहल सराहनीय है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में उपयुक्त वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है।

जेएसडब्ल्यू ग्रुप के श्री पार्थ मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हमें प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित किया है। हमारे समूह की प्रदेश में 4500 करोड़ रूपये के निवेश की योजना है। इसके अंतर्गत पन्ना में सीमेंट प्लांट और पीथमपुर में 1500 करोड़ की लागत से पेंट की इकाई लगाई जा रही है।

रिलायंस ग्रुप के श्री निखिल आर. मेसवानी ने कहा कि दिसम्बर 2023 तक प्रदेश की सभी तहसीलों में 5जी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। किफायती डिजिटल सुविधाओं से छात्रों, किसानों और आम आदमी को लाभ होगा। रिलायंस ग्रुप राज्य में अब तक 22 हजार 500 करोड़ का निवेश कर चुका है तथा 40 हजार करोड़ के निवेश की योजना है।

बजाज फिनसर्व के श्री संजीव बजाज ने कहा कि बजाज समूह का भविष्य मध्यप्रदेश के भविष्य से जुड़ा है। हम प्रदेश के सामान्य व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए समर्पित हैं।

अवादा ग्रुप के श्री विनीत मित्तल ने कहा कि प्रदेश में टेलेंट पुल की सुविधा उपयुक्त है। देश के सभी भागों से आवागमन की सुविधा के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्तियों के लिए प्रदेश में निवास सुगम रहता है। प्रदेश का वातावरण भी लोगों को आकर्षित करता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की राज्य को 550 बिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता को देखते हुए हमारे समूह ने यहाँ निवेश का निर्णय लिया है।

अडानी ग्रुप के श्री प्रणव अडानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में विभिन्न राज्यों में प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्मित किया है। मध्यप्रदेश इसमें अग्रणी राज्यों में है। अडानी समूह 60 हजार करोड़ रूपये का निवेश करने जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। समूह द्वारा धार, गुना, दमोह, उज्जैन और इंदौर में फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। श्री अडानी ने सीमेंट और ऊर्जा के क्षेत्र में समूह योजनाओं की जानकारी दी। श्री अडानी ने कहा कि सद्भावना के साथ विकास के सिद्धांत के अनुरूप समूह शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के क्षेत्र में भी सक्रिय है।

गोदरेज समूह के श्री नादिर गोदरेज ने मध्यप्रदेश में गोदरेज समूह की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। फोर्स ग्रुप के श्री फिरोदिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने आभार व्यक्त किया।

नवीन एवं गैर परम्परागत क्षेत्रों में सहकारी समिति के गठन प्रक्रिया पर प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओ के अपेक्षा के अनुरूप नवीन एवं गैरपरम्परागत क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओ के गठन प्रक्रिया पर विभाग के कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण /कार्यशाला का आयोजन दिनांक 06.01.2023 को म0प्र0 राज्य सहकारी संघ के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित किया गया । प्रशिक्षण में प्रदेश के विभिन्न जिलो से सहकारिता विभाग में पदस्थ उपअंकेक्षको द्वारा भाग लिया गया प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से प्रशिक्षण को दो खण्डो में विभाजित किया गया। प्रशिक्षण में विषय की सारगर्भिता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विषयों पर विद्वान अतिथि वक्ताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। सर्वप्रथम नवीन सहकारी समितियों के गठन प्रक्रिया पर शासन की अपेक्षा में एवं निर्देशों के संबंध में श्री प्रदीप नीखरा सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। द्वितीय चरण के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं में सशक्तिकरण एफ.पी. ओ. गठन में नावार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका पर श्री ललित मौर्या, वरिष्ठ अधिकारी नावार्ड द्वारा अपना उद्बोधन दिया। तृतीय सत्र में सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप नवीन क्षेत्रो की संस्थाओ हेतु व्यवसायिक कार्य योजना/प्रोजेक्ट निर्माण एंव कियान्वयन विषय पर विख्यात चार्टड एकाउन्टेंट श्री मुकेश सिंह राजपूत द्वारा प्रतिभागियो को विस्तारपूर्वक समझाया गया। सामूहिक चर्चा हेतु अंत में राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ,महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह एवं श्री अविनाश सिंह सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों से विषय के संबंध में चर्चा कर नवीन गैरपरम्परागत क्षेत्रो में सहकारी संस्थाओं के गठन किये जाने हेतु प्रेरित किया। प्रशिक्षण का संचालन संघ की कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमति मीनाक्षी बान द्वारा एवं श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, श्री विक्रम मुजुमदार का सहयोग सराहनीय रहा।

नवीन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की सम्भावना सिवनी में जिला सहकारी सम्मेलन संपन्न

सिवनी। राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं म०प्र० राज्य सहकारी संघ मर्या० भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा सिवनी जिलें में एक जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न सहकारी संस्थाओं के सहयोग से नवीन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की सम्भावना विषय पर विभिन्न अतिथि व्यक्ताओं ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त कियें। राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक माननीय श्री आर०आर०रंजन एवं महा प्रबंधक माननीय श्री संजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथि सिवनी के माननीय विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन थे।

जिला सहकारी सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि सहकारिता आंदोलन के विकास के लिये नवाचार आज प्रदेश में एक सहकारी कांति का रूप लेता जा रहा है। नये उददेश्य के साथ नवीन क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के व्यापक स्वरूप पर विचार मंथन हो रहा है। इस सम्मेलन में हम इसी दिशा में मंथन करेंगे। विधायक महोदय ने अपने उदबोधन में नवीन सहकारी संस्थाओं के गठन और विकास में हर संभव सहयोग देने का विश्वास दिलाया।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सिवनी के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री अशोक तेकाम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारिता में नवाचार के विकास व विचार मंथन के लियें सहकारी सम्मेलन एक प्रभावी और प्रेरक मंच होता है जिससे एक सार्थक सोच बन सकती है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को जन आन्दोलन बनाने के लिये सहकारिता में नवाचार एक सशक्त माध्यम है।

जिला वनोपज संघ सिवनी दक्षिण के अध्यक्ष माननीय श्री घनश्याम सराठे ने वनोपज सहकारी समितियों की आर्थिक समस्याओं की चर्चा करते हुए कहा कि सहकारिता में नवाचार के अंतर्गत वनोपज सहकारी समितियों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये प्रयास होने चाहिए। वनोपज सहकारी समितियों को व्यापार करने के लिये अन्य क्षेत्र और सुविधायें भी प्रदान की जाने चाहिए।

माननीय श्री बी०सी०उईक सेवा निवृत्त संयुक्त पंजीयक ने कहा कि सफल सहकारिता के लिये आज नवीन सहकारी संस्थाओं के गठन की आवश्यकता है। लेकिन इन संस्थाओं के गठन और विकास के लिये प्रभावकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए और इसके लिये म०प्र० राज्य सहकारी संघ एक सशक्त माध्यम हो सकता है।

सम्मेलन मे विशेष अतिथि के रूप में सहकारिता के उपायुक्त माननीय श्री अखिलेश निगम ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश में सहकारिता में नवाचार के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे है। सहकारिता विभाग भी इस दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पिछले दिनों नवीन सहकारी संस्थाओं के गठन के लिये प्रभावकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गए।

विशेष अतिथि के रूप में मत्स्य विभाग की उप संचालक श्रीमती संध्या कुमार ने सुझाव दिया कि मछली पालन सहकारी समितियों के लिये भी सहकारिता में नवाचार के अंतर्गत प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होने सिवनी जिलें में मछली विभाग और सहकारी समितिओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।

विशेष विशेषज्ञ के रूप में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने नवीन क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं की सम्भावना पर सारगार्भित व्याख्यान दिया। श्री पाठक ने प्रदेश की सहकारिता में नवाचार के अंतर्गत अनके सहकारी संस्थाओं के गठन और विकास की चर्चा की और कहा कि इस संबंध में सक्रिय कोशिशें की जानी चाहिए

केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही०के०बर्वे ने कहा कि म०प्र०राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारिता विभाग के निर्देशानुसार सहकारी क्षेत्र मे नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित और विकसित किया जा रहा है। आज हम इस सम्मेलन में नवाचार के उन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करेंगे जिसके अंतर्गत नवीन क्षेत्र में नये उददेश्य के लिये कुछ सार्थक निष्कर्ष निकाला जा सकें।

सम्मेलन के आयोजन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मत्स्य विभाग, दुग्ध सहकारी संघ सहित जिला सहकारी संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। श्री एन.डी. कटरे, प्रशासक, श्री पी.के. सूर्यवंशी प्रबंधक जिला सहकारी संघ के योगदान की भी विशेष चर्चा हुई।

सम्मेलन की शुरूआत सरस्वती पूजन से हुई एवं अतिथिओं का स्वागत पुष्पाहार और स्मृति चिन्ह से केन्द्र के प्राचार्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही०के०बर्वे एवं अन्त में आभार प्रदर्शन केन्द्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शोभित ब्यौहार द्वारा किया गया। सम्मेलन के आयोजन में श्री एन०पी०दुबे, पीयूष रॉय, अखलेश उपाध्याय, जयकुमार दुबे, हिदेश राय, बाबूलाल कुशवाहा एवं अमरसिंह कुशवाह का सहयोग सराहानीय रहा।

सहकार से समृद्धि के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किया 3 नए सहकारी संगठनों का निर्माण

नई दिल्ली. देश का सहकारिता क्षेत्र सीधा ग्रामीण क्षेत्र और किसानों, कृषि के उत्पादन और किसानों की आमदनी से जुड़ा है. इसी क्षेत्र से अब किसानों को और लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 सहकारी संगठनों को मंजूरी दे दी है. सरकार ने साल 1982 में को-ऑपरेटिव एक्ट और साल 1987 में ट्राइफेड बनाया था. इस तरह 35 साल के लंबे इंतजार के बाद अब नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल लेवल को-ऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेशनल मल्टी स्टेट सीड को-ऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की जाएगी.

सहकार से समृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने इन 3 संस्थाओं का गठन करने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय और सरकार के पूरे सहयोग से किसानों की उपज को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक्सपोर्ट करने का प्लान है. साथ ही उपज की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है.

देश में 8 लाख 50 हजार पंजीकृत सहकारिता संघ है, जिसमें करीब 29 करोड़ मेंबर है. इन सदस्यों में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से और किसान ही है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि देश में जैविक उत्पादन की काफी क्षमता है, जिसे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए नेशनल लेवल को-ऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर से किसानों को उत्पादन क्षेत्र के नजदीक ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनमें सस्ती दरों पर जैविक उत्पादों की जांच, सर्टिफिकेशन और तकनीकी सहयोग देना शामिल है.

इससे किसानों को अपने जैविक उत्पादों की सही मार्केटिंग और उचित दाम हासिल करने में भी मदद मिलेगी. वहीं नेशनल मल्टी स्टेट सीड को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किसानों को सीड का उत्पादन और बिक्री, बीज बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटिड से भी मदद

नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटिड नामक नई संस्थागत सोसाइटी के जरिए भी ट्रेडिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन, के साथ-साथ किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी गाइडेंस दी जाएंगी. इस संगठन के जरिए सरकार की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को भी सहकार से जोड़ा जाएगा.

ऑनालइन पेमेंट से जुड़ेंगे किसान

हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में Rupay डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई इंसेटिव स्कीम को भी मंजूरी दी है. इस स्कीम के जरिए डिजिटल पेमेंट को अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME Sector) , अन-ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ-साथ किसान और मजदूरों तक ले जाना संभव हो पाएंगा. इस स्कीम के लिए भी केंद्र सरकार ने 2,600 करोड़ मंजूर किए हैं.

सहकारिता में सहकारी अधिनियम एवं नियम का ज्ञान आवश्यक-राठौर

रतलाम। किसी भी संस्था में बैठक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैठक में ही सभी महत्व– पूर्ण निर्णय लिये जाते है। सहकारी संस्थाओं में बैठक की नियत समय–सीमा होती है। सहकारिता में नियम कानून होते है उनका ज्ञान होना आवश्यक है। नेतृत्व के विकास में भी बैठकों का महत्व होता है। उक्त विचार सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के पूर्व प्राचार्य के.एल. राठौर ने जावरा में राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, रतलाम द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतिम दिन व्यक्त किए। श्री राठौर ने सहकारी अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी भी दी।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के पूर्व प्राचार्य, निरंजन कुमार कसारा ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में समस्त सदस्य समस्त गतिविधियों के सृजनकर्ता होते है। कुशल नेतृत्व व प्रबंधन से आर्थिक समृद्धि व सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतिथि वक्ता राष्ट्रीय सहकारी परियोजना के प्रशिक्षक गिरीराजसिंह राठौर ने सहकारी नेतृत्व के प्रकार, उनके महत्व, नेतृत्व के गुण–दोष तथा कर्मचारियों में नेतृत्व के विकास पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजक संस्था जिला सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिरूद्ध शर्मा ने अंकेक्षण एवं कर–निर्धारण पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया। अंत में रोला सोसायटी के प्रबंधक भूपेन्द्र सिंह तोमर ने सहकारिता व राष्ट्रीयता पर अपनी कविताओं का पाठ किया। संस्था प्रबंधक कन्हैयालाल परमार ने भी संबोधित किया। संचालन अनिरूद्ध शर्मा ने एवं आभार जिला सहकारी संघ के जनसंपर्क अधिकारी पिंकेश भटट ने माना।

महिला सशक्तिकरण एवं विकास विषय पर प्रशिक्षण आयोजित

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल में 5 जनवरी 2023 को सहकारिता विभाग की महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण में कुल 42 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। प्रशिक्षण का प्रमुख उददेश्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को एक कदम और आगे बढाना था।

किसी भी महिला के सशक्तिकरण की दिशा में उसका पहला कदम शिक्षित होना , दूसरा कदम आत्मनिर्भर होना रहेगा ,एवं तीसरा कदम होगा सुरक्षित होना। किसी भी विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी शिक्षित एवं आत्मनिर्भर तो हो गई हैं, लेकिन समाज में महिलाओं के प्रति बढ रहे विभिन्न अपराधों से स्वयं का बचाव कैसे करें। इस संबंध में कौन–कौन से कानून हैं। कैसे स्वयं को जागरूक एवं सतर्क रखें। इन सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण का शुभारंभ राज्य सहकारी संघ मुख्यालय भोपाल में मां सरस्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं संघ के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह के उदबोधन द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रीय अकादमी भोपाल की प्रशिक्षण अधिकारी श्रीमती शैफाली टाकलकर द्वारा महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न अपराधों , उनसे जुड़े विभिन्न कानूनों , उनसे बचाव के उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। डिजीटलाइजेशन के युग में बढ रहे सायबर क्राइम तथा अन्य प्रकरणों के संबंध में केस स्टडी पर भी चर्चा की गई । प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान भी किया गया।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में बी. एस.एस.कालेज भोपाल के प्रोफेसर डा. अतुल दुबे द्वारा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में मानसिक स्थिति पर होने वाले प्रभाव एवं स्वयं को इस स्थिति में मजबूत कैसे रखें आदि बातों पर प्रकाश डाला। डा.दुबे द्वारा विभिन्न कियाकलापों के माध्यम से इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन केन्द्र भोपाल के प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी द्वारा किया गया।

कार्यक्रम का समन्वय श्रीमती रेखा पिप्पल, व्याख्याता द्वारा किया गया। कार्यक्रम आयोजन में विशेष सहयोग श्री संतोष येड़े, श्रीमती मीनाक्षी बान, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री विक्रम मुजुमदार एवं अन्य स्टाफ का रहा।

सहकारिता विभाग के सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों के लिए कार्यालयीन कार्य निष्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण संम्पन्न

भोपाल। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के निर्देशों के अनुरूप सहकारिता में पदस्थ समस्त जिलो के सहायक ग्रेड–3 के कर्मचारियों का कार्यालयीन कार्य निष्पादन एवं गुणवत्ता विषय पर एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 09–01–2023 एवं 10.01.2023 को म.प्र. राज्य सहकारी संघ के भोपाल प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में 61 प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया प्रशिक्षण विषय पर आधारित विभिन्न विषय जैसे म0प्र0 मूलभूत नियम,सर्विस बुक, वेतन वृद्धि, अवकाश नियम, यात्रा भत्ता नियम, चिकित्सा पूर्ति, भण्डार कय नियम विषयो पर श्री यू.एस. ठाकुर सेवानिवृत्त उपसचिव (लेखा) द्वारा प्रतिभागियो को विस्तारपूर्वक समझाया गया। प्रशिक्षण में द्वितीय सत्र अंतर्गत पत्राचार डाक प्राप्ति एवं वितरण नोटशीट लेखन नस्तीकरण एवं प्रस्तुतीकरण,पत्र लेखन, अर्द्धशासकीय पत्र, आदेश विधि कक्ष कार्य रीडर/विधानसभा की जानकारी श्री अविनाश सिंह सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा दी गयी। प्रशिक्षण के तृतीय सत्र अंतर्गत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 म.प्र. सेवा आचरण नियम 1965 पर श्री श्री कुमार जोशी सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा प्रतिभागियों को समझाया गया। प्रशिक्षण में चतुर्थ सत्र के अंतर्गत कर्मचारियो के अधिकार कर्त्तव्य ,कार्य निष्पादन, सूचना का अधिकार अधिनियम पर श्री जे.पी.गुप्ता सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता द्वारा अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में कर्मचारियो में उत्पन्न तनाव के प्रबंधन पर एवं कार्यस्थल पर कुशलता बनाये रखने हेतु समय प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन पर विख्यात मोटी वेशनल स्पीकर श्रीमति रश्मि गोलिया द्वारा व्यवहारिक एवं व्याख्यान रूप में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया प्रशिक्षण के समापन पर संघ के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह द्वारा संपूर्ण प्रशिक्षण पर प्रतिभागियो से फीड बैक प्राप्त करते हुए वर्तमान में प्रशिक्षण के आवश्कता पर अपना विचार व्यक्त किया प्रशिक्षण के सत्र समन्वयक श्री गणेश प्रसाद मांझी प्राचार्य एवं श्री ए.के. जोशी (पूर्व प्राचार्य), श्री विक्रम मजूमदार लिपिक द्वारा सत्र संचालन में सहयोग प्रदान किया गया।

सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी अनिवार्य-एस.के. सिंह

रतलाम। सहकारी संस्थाएं सेवा के साथ–साथ लाभ भी अर्जित करें। संस्थाओं को परंपरागत व्यवसाय के साथ नए व्यवसाय भी प्रारंभ करने चाहिए जिससे संस्थायें आत्मनिर्भर बन सके। उक्त विचार उपायुक्त सहकारिता एस.के.सिंह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली व जिला सहकारी संघ मर्यादित, रतलाम द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के लिए जावरा में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मुख्य अतिथि ने व्यक्त किये। श्री सिंह ने कहा कि सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ–साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाना आवश्यक है क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

शीघ्र आयें प्रवेश पायें
म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल द्वारा संचालित
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध

PGDCA
(योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण)
कुल फीस 9100/-

DCA
(योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण)
कुल फीस 8100/-

संपर्क :-
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र
ई- 8/77 शाहपुरा ,त्रिलंगा ,भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158 Website-www.mpscu.in
Web Portal-www.mpscuonline.in Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित
(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)
सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)
माध्यम - ऑनलाईन
योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/ प्रवेश की अंतिम तिथि – 28 फरवरी 2023
कुल फीस - 20200/-
ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।
संपर्क :-
म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल
ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158
Website-www.mpscu.in, Web Portal-www.mpscuonline.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001
मो. 9424782856 , 8827712378
Email - ctcjabalpur@gmail.com
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव
जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201
9424782856 , 9755844511
Email - ctcnowgong@gmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।